भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2135

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की सकल नामांकन दर

2135. श्री रंजिब बिस्वालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ने वर्ष 2014-15 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी॰ई॰आर॰) के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कमतर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धरित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के साथ-साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा में 2012-13 से 2014-15 तक के वर्षों के सकल नामांकन के अनुपात नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) - प्रतिशत		
	समस्त	अ.जा.	अ.ज.जा.
2012-13	21.5	16.0	11.1
2013-14	23.0	17.1	11.3
2014-15*	23.6	18.5	13.3

*अनंतिम

सभी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सकल नामांकन अनुपात में गिरावट का कारण कुछेक सामाजिक ग्रुपों में गरीबी, पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं और जागरूकता की कमी हो सकता है। तथापि, अ.जा. और अ.ज.जा. के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

(ग) और (घ): 12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2017-18 तक देश के सकल नामांकन अनुपात 25.2 प्रतिशत तक बढ़ाने और वर्ष 2020-21 तक 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। अ.जा./अ.ज.जा/कम आय वर्ग के समूह के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने शिक्षा के लागत की पूर्ति हेतु उनके लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के एक बड़े तबके तक शिक्षा की सुविधा का विस्तार करने के साथ-साथ प्रतिभा की पहचान और जीवनपर्यन्त सीखने को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से आईसीटी के बेहतर प्रयोग के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में विचार किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई योजना अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का अनुमोदन किया गया जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में साम्यता, सुलभता और उत्कृष्टता प्राप्त करना है। यह योजना स्वायत्त कॉलेजों के विश्वविद्यालयों में प्रोन्नयन तथा क्लस्टर कॉलेजों का विश्वविद्यालय स्थापित करने, असेवित और अर्द्धसेवित क्षेत्रों में व्यावसायिक कॉलेज खोलने तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्षमता में वृद्धि करने जैसे कारकों के लिए अवसंरचना अनुदान का समर्थन करती है।

*****